

छज़ीसगढ़ में ऑपरेशन जारी, बीजापुर में सुरक्षाबलों ने 18 खूंखार नज़सलियों को मार गिराया, 3 जवान शहीद

बीजापुर ०४/१२ (संवाददाता): छज़ीसगढ़ के बीजापुर जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों और नज़सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद बृहस्पतिवार सुबह तक छह और नज़सलियों के शव बरामद किए गए। इलाके में अभियान अब भी जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मुठभेड़ में मारे गए नज़सलियों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। इस मुठभेड़ में राज्य पुलिस की इकाई जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के तीन जवानों की भी मृत्यु हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मारे गए 18 नज़सलियों में से 16 की पहचान खतरनाक माओवादियों के तौर पर हुई है, जिन पर कुल मिलाकर 1.30 करोड़ रुपये का इनाम

था। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने बताया कि करीब 12 घंटे तक रुक-रुक कर हुई गोलीबारी के बाद, बुधवार देर शाम तक 12 नज़सलियों के शव बरामद किए गए। सुंदरराज ने बताया कि इलाके में तलाश अभियान के दौरान बृहस्पतिवार सुबह तक छह और शव बरामद किए गए और इसके साथ ही मुठभेड़ में मारे गए नज़सलियों की संख्या बढ़कर 18 हो गई, जिनमें नौ महिलाएं भी शामिल हैं। सुंदरराज ने बताया कि अभियान में दंतेवाड़ा और बीजापुर के डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि यह अभियान इलाके में माओवादियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन और पीएलजीए कंपनी

नंबर दो की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ बुधवार लगभग नौ बजे भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के तहत कचीलवार-पोटेनार गांव के जंगल में शुरू हुई तथा बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे तक चली। उन्होंने कहा, हमारे सुरक्षाबलों ने माओवादियों की गोलीबारी का बहादुरी से जवाब दिया, लेकिन दुर्भाग्य से डीआरजी बीजापुर के हमारे तीन बहादुर जवान इस दौरान शहीद हो गए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मुठभेड़ में जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल मोनू वडाड़ी, कांस्टेबल दुकारू गोडे और जवान रमेश सोड़ी बीजापुर जिले के निवासी थे। इस दौरान डीआरजी के सहायक उप निरीक्षक समेत दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं।



उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया है।

अधिकारी ने बताया कि वेल्हा माओवादियों की पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) की कंपनी नंबर दो के कमांडर के तौर पर सक्रिय था और सुरक्षाबलों पर हमलों की कई घटनाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि इन वारदातों में 2020 में सुकमा के मिनपा में हुई घटना भी शामिल है, जिसमें 17 सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु हुई थी।

वेल्हा के सिर पर आठ लाख रुपये का इनाम था। सुंदरराज ने बताया कि मारे गए 15 अन्य नज़सली वरिष्ठ कैडर थे और उन पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम था, जबकि बाकी दो मारे गए कैडर की पहचान अभी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मौके से एक लाइट मशीन गन, चार एके-47 राइफल, चार सिंगल लोडिंग राइफल (एसएलआर), एक इंसास राइफल, दो .303 राइफल, चार सिंगल शॉट राइफल, दो बैरल

ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) और एक भरमार बंदूक बरामद की गई है। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा, रेडियो, स्कैनर, मल्टीमीटर, हैंड ग्रेनेड, सेज्टी ज्यूज, माओवादी साहित्य, यूनिफॉर्म, मेडिकल वस्तु और दूसरा सामान भी जप्त किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस साल अब तक छज़ीसगढ़ में मुठभेड़ में 281 नज़सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 252 बीजापुर समेत सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में मारे गए।

वहीं 27 नज़सली रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत गरियाबंद जिले में मारे गए। राज्य के दुर्ग क्षेत्र के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दो नज़सली मारे गए। सुंदरराज ने बताया कि जनवरी 2024 से बस्तर क्षेत्र में नज़सल विरोधी अभियान के दौरान 469 माओवादियों का

शव बरामद किया गया, जिनमें कई माओवादी नेता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों के बीच मजबूत तालमेल की वजह से इलाके में माओवादियों के बचे हुए टिकानों के खिलाफ अभियान और भी तेज़ तथा असरदार हो गए हैं। अधिकारी ने कहा कि इन कोशिशों का मुख्य मकसद दूर-दराज के इलाकों को माओवादियों के असर से आजाद कराना, शांति और व्यवस्था को मजबूत करना तथा इलाके में सबको साथ लेकर चलने वाले और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है - एक शांतिपूर्ण और नज़सल-मुक्त बस्तर। मौजूदा परिस्थितियों में माओवादी संगठन पूरी तरह घिर चुका है और अब उसके पास हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं

बचा है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के साथ, इस साल अब तक राज्य में माओवादी हिंसा में 23 सुरक्षाकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें उनके साथ होने वाली मुठभेड़ें भी शामिल हैं। इससे पहले आज बीजापुर पुलिस लाइन में शहीद वाटिका में जान गंवाने वाले तीन जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्थानीय विधायक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मृत जवानों के परिजन वहां मौजूद थे। इसके बाद, उनके पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थानों पर भेज दिए गए। केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए 31 मार्च, 2026 तक की समयसीमा तय की है।

योगीराज में घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू, उज़र प्रदेश में रोहिंग्या, बांग्लादेशी खोजे जाएंगे, होगी कार्रवाई

लखनऊ ०४/१२ (संवाददाता): उज़र प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कथित रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है और राज्य के हर संभाग में हिरासत केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी किए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 शहरी स्थानीय निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये सूचियाँ आगे की जाँच के लिए संबंधित आयुक्तों और महानिरीक्षकों को सौंपी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने सभी 18 संभागों के संभागीय आयुक्तों और 18 रेंजों के पुलिस महानिरीक्षकों को प्रत्येक संभाग में एक निरोध केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है ताकि अवैध प्रवासियों को उनके निर्वासन तक रखा जा सके। यह निर्देश कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सभी



जिलाधिकारियों (डीएम) को घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। इससे पहले, जिलाधिकारियों को जिलों में अस्थायी निरोध केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। आयुक्तों और पुलिस महानिरीक्षकों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान जारी रखने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संबंधित नगर निगमों से सूचियाँ प्राप्त होते ही, आयुक्तों और पुलिस महानिरीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

गया है कि उनके संभाग या क्षेत्र में सभी अवैध प्रवासियों का पता लगाया जाए, उनका सत्यापन किया जाए और उचित औपचारिकताओं के अनुसार उन्हें निर्वासित करने से पहले हिरासत केंद्रों में रखा जाए। एक सरकारी प्रवक्ता ने पुष्टि की कि 22 नवंबर को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से ही जिलों में रह रहे/रोजगार कर रहे अवैध प्रवासियों की पहचान और पता लगाने के लिए ज़िले के डीएम और एसपी अभियान चला रहे हैं। 23 नवंबर को जारी एक बयान में, सरकार ने कहा था कि नेपाल सीमा और प्रमुख शहरी केंद्रों पर कार्रवाई में तेज़ी आई है।

नयी दिल्ली ०४/१२ (संवाददाता): रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को दो दिन के स्टेट विज़िट पर नई दिल्ली पहुंचे। यह विज़िट लगभग आठ दशक पुरानी इंडिया-रूस पार्टनरशिप को और बढ़ाएगी। नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशियन लीडर को गले लगाकर रिस्वी किया और इंडिया में उनका गर्मजोशी से वेलकम किया।

इसके बाद, दोनों लीडर एक ही कार में सफर करके 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे -- जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल घर है। मोदी ने पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर भी होस्ट किया, जो पिछले साल जुलाई में मॉस्को विज़िट के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा की गई मेहमाननवाजी के बदले में था। मोदी समिट की जगह हैदराबाद हाउस में रूसी लीडर और उनके डेलीगेशन के लिए वर्किंग लंच



भी होस्ट करेंगे।

मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, पुतिन सुबह राजघाट भी जाएंगे। समिट के बाद, पुतिन रूस के सरकारी बॉडकास्टर का नया इंडिया चैनल लॉन्च करेंगे, जिसके बाद वह प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके सज़्मान में रखी गई सरकारी दावत में शामिल होंगे। रूसी लीडर के शुक्रवार रात करीब 9 बजे भारत छोड़ने की उज्ज्मीद है। समिट के बाद, पुतिन रूस के सरकारी बॉडकास्टर का नया इंडिया चैनल लॉन्च करेंगे, जिसके बाद

वह प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके सज़्मान में रखी गई सरकारी दावत में शामिल होंगे। समिट की बातचीत में, नई दिल्ली से उज्ज्मीद है कि वह भारत द्वारा रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने से बढ़ते ट्रेड डेफिसिट को दूर करने पर ज़ोर देगा।

रूस के प्रेसिडेंट का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वॉशिंगटन के भारतीय सामान पर 50 परसेंट का भारी टैरिफ लगाने के बाद भारत-रु के रिश्ते शायद पिछले दो दशकों के सबसे बुरे दौर से गुज़र रहे

हैं, जिसमें नई दिल्ली के रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 परसेंट लेवी भी शामिल है। समिट में भारत के रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिकी प्रतिबंधों के असर पर चर्चा होने की संभावना है।

क्रेंमलिन के स्पोज्सपर्सन दिमित्री पेसकोव ने मंगलवार को कहा कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को देखते हुए नई दिल्ली की रूस से कच्चे तेल की खरीद थोड़े समय के लिए कम हो सकती है, लेकिन साथ ही, उन्होंने कहा कि मॉस्को सप्लाई बढ़ाने के लिए

मौसम का मजा लीजिये-विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध किया प्रदर्शन

नयी दिल्ली ०४/१२ (संवाददाता): दिल्ली-एनसीआर और उज़र भारत के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर स्थित मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सांसद ऑर्ज्सीजन मास्क पहने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करने वाले एक बैनर पकड़े हुए दिखाई दिए, जिस पर लिखा था, मौसम का मज़ा लीजिए। बैनर पर यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में दिए गए संबोधन के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने यह बात कही थी। नारे लगाते हुए, नेताओं ने वायु प्रदूषण पर संसद में चर्चा की मांग की।

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी संसद भवन



के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। इससे पहले आज, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रदूषण को लेकर सरकार की आलोचना की और एएनआई को बताया कि विपक्षी सांसद केंद्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि बाहर के लोग इसे समझ नहीं सकते... ऐसा लगता है जैसे दिल्ली और कुछ अन्य शहरों को गैस चैंबर में बदल दिया गया है और नागरिकों को वहीं रखा जा रहा है। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार इसके लिए

जि़म्मेदार हैं। विपक्षी सांसद आज संसद के मकर द्वार पर इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे।

संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, मनीष तिवारी और विजयकुमार उर्फ ??विजय वसंत ने उज़र भारत में वायु गुणवत्ता पर चर्चा के लिए नोटिस पेश किए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र से प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का आग्रह किया। टैगोर ने लोकसभा महासचिव

को भेजे अपने नोटिस में कहा, सरकार पंगु बनी हुई है, कार्रवाई की बजाय सलाह जारी कर रही है, समाधान की बजाय समितियाँ बना रही है, समन्वित राष्ट्रीय रणनीति की बजाय नारे लगा रही है।

जबकि इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि प्रदूषण से कैंसर, गुर्दे की बीमारी, जठरांत्र संबंधी विकार और मधुमेह जैसी चयापचय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, यह सरकार प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित करने से इनकार कर रही है।

रेलवे का बड़ा फैसला-तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी का इस्तेमाल, ऐसे मिलेगा कन्फर्म टिकट

नयी दिल्ली ०४/१२ (संवाददाता): आम उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे द्वारा एक ओटीपी-आधारित तत्काल आरक्षण प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया था। सबसे पहले, रेलवे ने जुलाई 2025 में ऑनलाइन तत्काल टिकटिंग के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण शुरू किया। दूसरा, बुकिंग के पहले दिन सभी सामान्य आरक्षणों के लिए एक ओटीपी-आधारित ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली अक्टूबर 2025 में लागू की गई थी। दोनों पहलों को आम उपयोगकर्ताओं द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है, जिससे आरक्षण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित हुई है।

रेलवे ने 17 नवंबर 2025 को आरक्षण काउंटरों पर बुक किए गए टिकटों के लिए ओटीपी-आधारित तत्काल



आरक्षण प्रणाली के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की। अब तक, इस प्रणाली को कुल 52 ट्रेनों तक बढ़ा दिया गया है।

इस प्रणाली के तहत, आरक्षण काउंटर पर तत्काल टिकट बुक करते समय, यात्री को आरक्षण फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होता है। अगले कुछ दिनों में, काउंटरों पर ओटीपी आधारित तत्काल आरक्षण प्रणाली शेष सभी ट्रेनों के लिए लागू कर दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य तत्काल सुविधा के दुरुपयोग को रोकना और यह

सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन सुधारों के समानांतर, भारतीय रेलवे ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे पहले चार्ट तैयार करने के लिए अपने आरक्षण कार्यप्रवाह में एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है। वर्तमान चार घंटे की खिड़की अज़रर यात्रियों को अनिश्चित बनाती है, खासकर दूरदराज या उपनगरीय स्थानों से यात्रा करने वालों को।

कलिंग समाचार

THE KALINGA SAMACHAR

(A Hindi Daily News Paper)

PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH

FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT

AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16

ROURKELA, PH. 0661-2646999

PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)

E-mail: thekalingasamachar@gmail.com



विविध समाचार

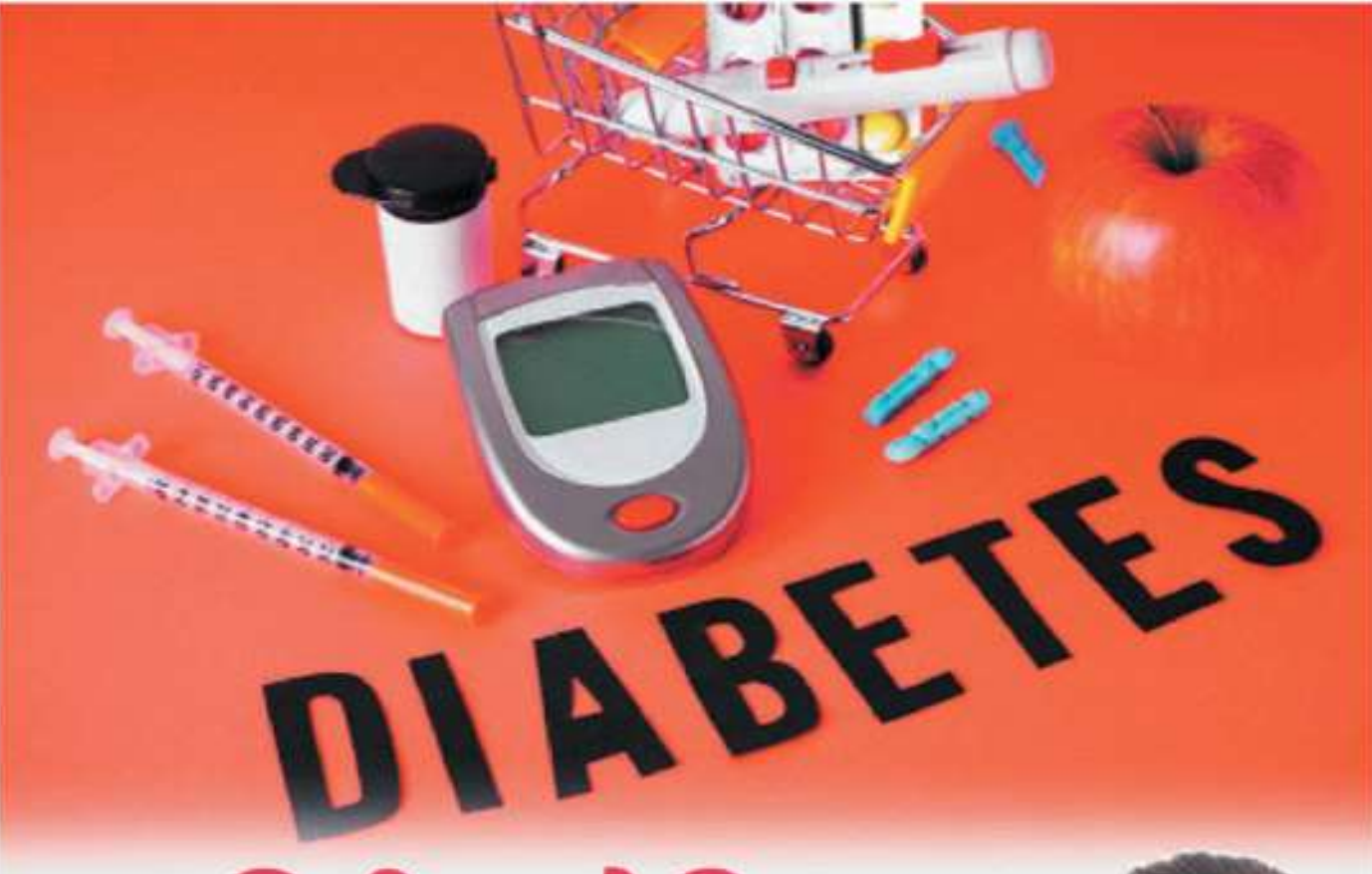


सर्दियों में बच्चों की सेहत रहेगी चकाचक, खिलाएं ये सुपरफूड्स

सर्दियों में बच्चों की इम्युनिटी को मजबूत रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों को ठंड और संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। सही आहार देकर आप उनकी इम्युनिटी को मजबूत कर सकते हैं। आप बच्चे को स्वस्थ और एक्टिव रखने के लिए किसी विकल्प की तलाश में हैं तो हम आपको एक्सपर्ट के बताए कुछ सुपर फूड्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप उनकी डाइट में इन्हें शामिल कर कर ना सिर्फ इम्युनिटी बूस्ट कर सकते हैं बल्कि सेहत के अन्य पहलुओं को भी बेहतर बना सकते हैं।

सर्दियों में बच्चों की इम्युनिटी मजबूत रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है, ऐसे में आप इन चीजों को खिलाकर आप उन्हें स्वस्थ और एक्टिव बना सकते हैं।

- बच्चों की इम्युनिटी कैसे मजबूत करें?**
- बच्चे की डाइट में विटामिन ए और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इसके लिए आप बीटरूट खिला सकते हैं। इसमें विटामिन ए और सी दोनों होते हैं। गाजर, आंवला संतरा कीवी, शकरकंदी, यह सभी इम्युनिटी बूस्ट करने वाले फल हैं।
 - बच्चे को नट्स और सीड्स जरूर दें। यह बेहतरीन पोषण का स्रोत होते हैं। इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो ना इम्युनिटी को मजबूत बनाते हैं बल्कि शरीर के विकास के लिए भी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बादाम और अखरोट खिलाएं। इसके अलावा किया सीड्स भी खिलाएं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर होते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो नट्स को चिमोकर उसका छिलका उतार लें, फिर पेस्ट बनाकर डाइट में ऐड करें।
 - बच्चों की डाइट में प्रोबायोटिक्स जरूर शामिल करें। इसके लिए दही केफिर फर्मेंटेड फूड्स खिलाएं, इससे इम्युनिटी मजबूत होती है। पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है।



डायबिटीज मेलिटस क्या होता है?

डायबिटीज मेलिटस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। यह दो मुख्य प्रकारों में पाया जाता है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज।

डायबिटीज एक गंभीर रोग है, यह खराब लाइफस्टाइल जीने का परिणाम होता है, यह समस्या तब होती है जब शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है या शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इससे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। आज इस बीमारी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्या आप

डायबिटीज मेलिटस के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है डायबिटीज मेलिटस।
डायबिटीज मेलिटस क्या होता है?
एक्सपर्ट बताते हैं कि जब शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो यह यूरिन के जरिए निकलने लगता है, जब ग्लूकोज यूरिन से निकलने लगता है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोसुरिया साथ में उसका बैलेंस करने के लिए सेल्स में से वॉटर भी एक्ससीट होता है। इससे शरीर में यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिसे पॉली यूरिया के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में आपको बार-बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है। यह डायबिटीज मेलिटस के लक्षण होते हैं।

कैसे करें बचाव?

- सही लाइफस्टाइल का चुनाव
- नियमित रूप से एक्सरसाइज करें।
- फाइबर रिच डाइट लें।
- ब्लड शुगर की निगरानी करें



डाइट में शामिल करें इस हरे पत्ते का पानी, मिलेंगे ये फायदे

बथुआ का पानी आपके डाइजेशन को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देता है।

साग कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक है सर्दियों में मिलने वाला बथुआ का साग, यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे आमतौर पर सब्जी के रूप में खाया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर आप बथुआ साग का पानी पिएं तो आपकी सेहत को फिटना लाभ होगा? आइए समझते हैं बथुआ साग का पानी पीने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं।

बथुआ का पानी पीने के फायदे

- बथुआ का पानी पीने से सर्दियों में आपकी इम्युनिटी मजबूत हो सकती है। इसमें विटामिन ए, सी, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे मौसमी बीमारियों से बचाव होता है।
- इसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है, ऐसे में अगर आपको खून की कमी है तो आप इरॉन्स पानी पी सकते हैं, इससे एनीमिया में फायदा हो सकता है। खून की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है।
- बथुआ का पानी पीने से एसिडिटी कब्ज की समस्या ये भी फायदा मिलता है इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है।

बथुआ का पानी कैसे तैयार करें?

- इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए आप बथुआ को 3 से 4 पानी साफ से धो लें।
- अब एक बर्तन में पानी डाल कर बथुआ को उबाल लें
- तैयार है बथुआ का पानी आप इसे गर्म या ठंडा करके पी सकते हैं।

कब पड़ती है इंसुलिन लेने की जरूरत

डायबिटीज एक गंभीर रोग है। इसे बोलचाल की भाषा में शुगर का जाता है। डायबिटीज सब होता है जब आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या शरीर इसका उपयोग नहीं कर पाता है। डायबिटीज का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसे आप सही जीवन शैली और दवाई लेकर करके कंट्रोल में कर सकते हैं। वहीं कुछ कंडीशन में मरीज को इंसुलिन भी दिया जाता है। आइए जानते हैं डायबिटीज में इंसुलिन लेने की जरूरत कब पड़ती है इस बारे में हम जानकारी दे रहे हैं।

डायबिटीज में इंसुलिन लेने की जरूरत कब पड़ती है?

डायबिटीज दो प्रकार की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज है और दूसरा टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जब शरीर इंसुलिन का उत्पादन करना पूरी तरह से बंद कर

देता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लेने की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर में नेचुरल रूप से इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है। यह आमतौर पर बच्चों या युवा लोगों में होता है। बता दें की इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज यानी कि शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर टाइप 2 डायबिटीज में डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाता है तब भी इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन थेरेपी को आमतौर पर तब शुरू किया जाता है जब प्रारंभिक कार्टिंग प्लाजमा ग्लूकोज 250 से अधिक हो या HbA1c 10% से अधिक हो। इंसुलिन आमतौर पर तब आवश्यकता होती है जब रक्त शर्करा का स्तर 200 से ऊपर हो। हालांकि यह निर्णय डॉक्टर पर निर्भर करता है कि इंसुलिन कब शुरू करना है। डॉक्टर आपके रक्त शर्करा के स्तर, लक्षणों और अन्य स्वास्थ्य कारकों को ध्यान में रखते हुए इंसुलिन थेरेपी शुरू करने का निर्णय लेते हैं।



जब भी हमारे शरीर में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है या शरीर में किसी बीमारी की शुरुआत होती है, तो इसके लक्षण साफ नजर आने लगते हैं। अगर आप इन लक्षणों को समय पर पहचान लें, तो आने वाले वक्त की मुश्किलों से बचा जा सकता है। आपके हाथ भी कई जरूरी चीजों के बारे में बताते हैं। नाखूनों का जल्दी टूटना, नाखूनों का पीला होना और भी कई चीजें, शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी का संकेत देती हैं।

सेहतमंद रहने के लिए, शरीर के सभी अंगों का ठीक से काम करना और शरीर में सभी विटामिन्स, मिनेरल्स और हार्मोन्स का लेवल सही होना जरूरी है। जब भी हमारे शरीर में किसी बीमारी के पनपने की शुरुआत होती है या किसी जरूरी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो इसके कुछ लक्षण शरीर में नजर आने

टूटे नाखून से लेकर रूखी हथेलियों तक, इन जरूरी चीजों की कमी का संकेत दे सकते हैं आपके हाथ

लगते हैं। कमजोरी महसूस होना, हमेशा थकान रहना, डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें या शरीर में दर्द रहना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन, असल में ये चीजें सेहत से जुड़ी जरूरी जानकारी देती हैं। हमारे नाखून और हाथ भी सेहत से जुड़े कई इशारे करते हैं, जिन्हें समझकर अगर हम अपने डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करें, तो हम सेहतमंद रह पाएंगे। हमारे हाथ सेहत के बारे में क्या कुछ कहते हैं और शरीर में किन जरूरी न्यूट्रिएंट की कमी का इशारा करते हैं, इस बारे में एक्सपर्ट से जानते हैं।

- एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपने नाखून टूटते हैं यानी बीच-बीच में टूटें हुए हैं, तो शरीर में विटामिन बी7 (बायोटिन), विटामिन बी12 और

कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसकी वजह से नाखून कमजोर होने लगते हैं। अगर आपके नाखून पीले हो रहे हैं, तो आपको इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पीले नाखून, शरीर में आयरन की कमी यानी एनीमिया और दिवर् के टीक तरह से काम न करने को दिखाते हैं। अगर आपके नाखून अधिक पीले हैं, तो यह पीलिया का संकेत भी हो सकता है।

- सर्दियों में हाथों में रूखापन आम बात है। लेकिन, अगर आपके हाथ हमेशा ड्राई करते हैं, तो शरीर में हार्मोनल इबैलेन्स का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है आपके शरीर में एस्ट्रोजन की कमी हो सकती है।
- अगर आपके हाथ बहुत अधिक ठंडे रहते



हैं, तो यह शरीर में खून की कमी का संकेत हो सकता है। यह हाइपोथायराइड या लो थायराइड फंक्शन का भी संकेत हो सकता है। अगर आपके हाथ अक्सर कांपते रहते हैं, तो यह विटामिन-बी 12 की कमी या हाइपोथायराइड का संकेत हो सकता है। अगर आपकी उंगलियां या हाथों के

ज्वाइट्स में दर्द होता है, तो इसके पीछे शरीर में एस्ट्रोजन या कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर आपको हथेलियों पर पीले धब्बे कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़े होने का संकेत हो सकता है। यह लिबर के टीक से काम न करने का संकेत भी हो सकता है।

- जिन लोगों को हाथों में सुई चुभती हुई महसूस होती है, उनके शरीर में विटामिन-बी की कमी हो सकती है।
- अगर आपके नाखूनों पर लाइने नजर आ रही हैं, तो यह जिंक या आयरन की कमी का संकेत हो सकता है। इसकी वजह से नाखूनों पर सफेद पैटर्न भी नजर आ सकते हैं।

कलिंग समाचार



संपादकीय

शुक्रवार 05 दिसंबर 2025

बीएलओ की आत्महत्या चिंताजनक

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विवाद खत्म होने की जगह अब घातक होता जा रहा है। एसआईआर पर विपक्ष की आपत्ति को कुछ पल के लिए अलग रखें तो भी इस समूची प्रक्रिया में पूरे देश में अब तक 25 बीएलओ की मौतें सचमुच चिंता पैदा करने वाली हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक 34 मौतें हो चुकी हैं। अब आंकड़ें जो भी हों, अगर एक भी बीएलओ की मौत इस वजह से होती है कि उस पर एसआईआर करवाने का दबाव था या चुनिंदा लोगों के नाम काटने के लिए उसे धमकाया जा रहा था, तो यह एसआईआर की प्रक्रियागत खामी की ओर इशारा करती है। जिस पर तत्काल संज्ञान लेने की ज़रूरत है। गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश इन तमाम राज्यों में भाजपा सरकारें हैं जो पूरी तरह से एसआईआर के समर्थन में हैं, क्या इन राज्य सरकारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके राज्य में इस तरह अकाल मौतें हो रही हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सभी दल ऐसी मौतों पर अब चिंता जता रहे हैं। अभी गोंडा में ही एक मामला सामने आया है, जिसमें अपनी शादी से एक दिन पहले बीएलओ विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली। विपिन यादव के परिवार का कहना है कि एसडीएम और लेखपाल एसआईआर में ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव बना रहे थे। विपिन यादव ने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकालने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी गई। परिवार का आरोप है कि विपिन यादव से कहा गया था कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी खत्म कर दी जाएगी। जिसके बाद विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली। यह मामूली आरोप नहीं है और इसकी गहन जांच की ज़रूरत है। कांग्रेस ने इस पर लिखा भी है कि ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने पर लगे हैं और एसआईआर उसी का औजार है। ज्यादा जाजें पेपर विविध विषय पॉडकास्ट राजनीतिक चर्चा मंच युवा विशेष सामग्री अखबार बजट 2019 विश्लेषण खेल समाचार अपडेट राजनीतिक विश्लेषण बॉलीवुड समाचार संग्रह समाचार पत्र ज्यादा जाने मनोरंजन समाचार आर्थिक समाचार बुलेटिन बजट विश्लेषण सेवाएं क्षेत्रीय समाचार पत्र युवा विशेष सामग्री विविध समाचार साक्षात्कार संग्रह ई-पेपर सदस्यता कविता संग्रह पुस्तकें ई-पेपर एक्सेस वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा है कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो, वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा ? आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े-दलित-वंचित-गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर भाजपा अपनी मनमाफ़िक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या की जिं मेदार है। ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं और उसे भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए घेरा है। जिस पर भाजपा नेताओं ने कहा है कि ममता बनर्जी अपनी हार के बहाने बता रही हैं। इसी तरह अखिलेश यादव भी बीएलओ की मौतों पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि किस तरह इंडिया गठबंधन की जीती हुई सीटों पर वोट काटने की तैयारी हो रही है, तो भाजपा उनकी भी आलोचना कर रही है। यह प्रवृत्ति स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। विपक्ष के पास अभी कम राज्य हैं, या भाजपा की तुलना में उसका जनाधार कम है, तो इससे उसका राजनैतिक महत्व कम नहीं हो जाता। याद रहे कि लोकसभा में भाजपा खुद के बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि विपक्ष उस पर भारी पड़ गया। अगर विपक्षी नेता किसी मुद्दे पर ध्यान दिला रहे हैं तो सरकार का काम है कि उसे पूरी ईमानदारी से सुने। सरकार की तरह चुनाव आयोग की भी जि मेदारी है कि वह अपनी निष्पक्षता का यकीन सारे दलों को दिला पाए। फिलहाल लगता है कि चुनाव आयोग को विपक्ष के संदेहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर की समय सीमा में संशोधन न्यायपालिका से भी यही अपेक्षित है कि वह बीएलओ की अकाल मौतों का स्वतः संज्ञान ले। अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

के रवींद्रन शिखर

स मेलन में होने वाली चर्चाओं में बड़ी आर्थिक संभावनाओं पर भी बात होने की संभावना है, भले ही रक्षा और ऊर्जा सुर्खियों में छाप रहें। दोनों देशों के बीच व्यापार के आंकड़ों में पहले वृद्धि में तेज़ी दिखी, फिर कुछ समय के लिए ठहराव भी आया, जो लगातार बढ़ोतरी को अनलॉक करने के लिए ढांचागत दखल की ज़रूरत को दिखाता है। राजनीतिक इरादे और आर्थिक व्यावहारिक सोच का बढ़ता मेल भारत–रूस रिश्ते को नई र्तार दे रहा है, जिससे नई दिल्ली में होने वाला शिखर स मेलन एक ऐसी भागीदारी में एक अहम पल बन रहा है जिसने पहले ही दशकों के भूराजनीतिक बदलावों को झेला है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा, जिसे %स्पेशल और प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप% (विशेष और तरजीही भागीदारी) की शब्दवली में बताया गया है, दोनों तरफ़ से एक ऐसे एजेंडा को आगे बढ़ाने की इच्छा का संकेत देता है जो अब पहले की रुकावटों तक सीमित नहीं है और अब सिर्फ़ पुरानी मजबूरियों से बना नहीं है।

जबकि पिछले साल ज्यादातर बातचीत में तेल ही हावी रहा,वैश्विक ऊर्जा बाजार में हो रहे बदलाव और वाशिंगटन में चल रही बातचीत ने हाइड्रोकार्बन को लेकर दबाव कम कर दिया है, जिससे नई दिल्ली और मॉस्को अपना ध्यान रक्षा सहयोग और बड़े रणनीतिगत संबंधों पर केन्द्रित कर पा रहे हैं। इस बदलाव को मुमकिन बनाने वाला एक बड़ा

सर्वमित्रा सुरजन

दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की डिजिटल जासूसी के खिलाफ कड़े कानून हैं, लेकिन यहां तो मांझी ही नाव डुबोने वाले बने हुए हैं। वैसे इस फैसले पर अब बड़ी फोन निर्माता कंपनियां भी सहमत नहीं हैं। ऐप्पल अपने स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप प्रीलोड करने के आदेश का पालन करने की योजना नहीं बना रहा है। खबर है कि वह अपनी चिंताओं से भारत सरकार को अवगत कराएगा। मोदी सरकार तानाशाही कायम करने के नित नए तरीके ईजाद कर रही है। और यह काम इतनी चालाकी से किया जा रहा है कि जनता को लगता है कि सब उसके भले के लिए है। जहरीली हवा में सांस लेते और जहरीला पानी पीते हुए भी जनता जब प्रधानमंत्री को यह कहते सुनती है कि मौसम का मज़ा लीजिए, तो उसे लगता है कि सांसें गिरवी रख देना ही राधर्म है। चीन के बाद नेपाल भी भारत के इलाकों पर अपना कब्जा दिखा चुका है, लेकिन जब मोदी कहते हैं कि ये नया भारत है, जो झुकता नहीं है, तो जनता गलवान से लेकर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर तक सब भूल जाती है। विपक्षी दलों पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए मोदी जब खुद बीजेपी और सहयोगी दलों में बेटे-बेटियों और रिश्तेदारों को आगे बढ़ाते हैं तो जनता को यह राजनैतिक चातुर्य लगता है। ऐसे दर्जनों उदाहरण पेश किए जा सकते हैं, जिसमें मोदी की कथनी और करनी में जमीन–आसमान जैसा अंतर दिखाई देता है। लेकिन जनता फिर भी भ्रमित हो चुकी

इस जुए में अब मोदी

सरकार ने लोगों के मोबाइल सेट के जरिए जासूसी का पांसा फेंका है। वो भी बेहद लुभावने नाम के साथ। संचार साथी ऐप, नाम से लगेगा हमारा कोई साथी है, यानी सुख–दुख में साथ देने वाला। लेकिन ये साथी तो असल में आस्तीन का सांप बनेगा, जो कब डसेगा कहा नहीं जा सकता। सबसे अच्छा स्मार्टफोन सरकार ने पिछले सप्ताह मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं को निर्देश दिया है कि भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए या आयात किए गए सभी नए मोबाइल हैंडसेट में 90 दिनों के भीतर संचार साथी ऐप प्री–इंस्टॉल हो जाए। दूरसंचार विभाग के निर्देश में अनिवार्य किया गया है कि भारत में

बदलाव करूड सप्लाई को लेकर उ मीदों का पुनर्समायोजन है। वैश्विक तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव और भारत की ऊर्जा टोकरी की बदलती बनावट ने ऐसा माहौल बना दिया है, जहां रूसी हेवी करूड बनाम अमेरिकी लाइट करूड को लेकर टकराव अब ज़रूरी नहीं रहा। भारत की कई अन्य आपूर्तिकर्ताओं से आयात संतुलित करने की क्षमता, और खरीदे जाने वाले तेल के ग्रेड के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा की कमी ने, वाशिंगटन और मॉस्को के साथ उसकी भागीदारी के बीच टकराव की गुंजाइश कम कर दी है। बदले में, इसने भारत के राजनयिक बैंडविड्थ से एक बड़ा बोझ कम कर दिया है, जिससे नीति योजनाकार रूस के साथ सहयोग के पुराने तरीकों पर फिर से विचार कर सकते हैं और किसी दूसरे भागीदार को नाराज़ करने की चिंता किए बिना नए तरीके खोज सकते हैं।

इस बदलाव से बनी जगह खास तौर पर रक्षा सहयोग में साफ़ दिखती है, जो लंबे समय से भारत–रूस समीकरण का सबसे अहम हिस्सा रहा है। दोनों सरकारों ने माना है कि रक्षा संबंधों को गहरा करना दिल्ली शिखर स मेलन का केन्द्र होगा। उ मीद है कि चर्चा पारंपरिक खरीदार–बिक्रीकर्ता गत्यात्मकता से आगे बढ़ेगी, जिसने शीतयुद्ध काल के बाद से सैन्य संबंधों को आकार दिया है। भारत, जो अब रक्षा उत्थान में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए अपनी कोशिशों में ज्यादा जोर दे रहा है, ऐसे मॉडल खोज रहा है

मोबाइल का साथी या आस्तीन का सांप

है, क्योंकि मोदी के प्रचार तंत्र ने जमीन–आसमान के अंतर को उस क्षितिज की तरह पेश किया है, जहां जमीन–आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं।

रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटकते मृग की तरह जनता की हालत हो चुकी है। यह सब प्रचारतंत्र की बाजीगरी है। बहुत पहले जब देश में शुद्ध देसी घी ही खाया जाता था, तब वनस्पति घी बेचने के लिए बाजारों में मु त के पकवान परोसे जाते थे। बेचने और ठगने का यही तरीका अब राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसमें जनता केकेवल ठगा नहीं रही है, बल्कि राजनीति के चौपड़ में लोकतंत्र को दांव पर लगा रही है। कुरुसभा की तरह संवैधानिक संस्थाएं आंख पर पट्टी बांधे या देखे को अनदेखा कर जुए के इस तमाशे का मजा ले रही हैं।

इस जुए में अब मोदी सरकार ने लोगों के मोबाइल सेट के जरिए जासूसी का पांसा फेंका है। वो भी बेहद लुभावने नाम के साथ। संचार साथी ऐप, नाम से लगेगा हमारा कोई साथी है, यानी सुख–दुख में साथ देने वाला। लेकिन ये साथी तो असल में आस्तीन का सांप बनेगा, जो कब डसेगा कहा नहीं जा सकता। सबसे अच्छा स्मार्टफोन सरकार ने पिछले सप्ताह मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं को निर्देश दिया है कि भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए या आयात किए गए सभी नए मोबाइल हैंडसेट में 90 दिनों के भीतर संचार साथी ऐप प्री–इंस्टॉल हो जाए। दूरसंचार विभाग के निर्देश में अनिवार्य किया गया है कि भारत में

जिनमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त विनिर्माण और साइबर क्षमताओं, स्पेस आधारित संपदा और एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम जैसे उभरते हुए क्षेत्र में लंबे समय तक सहयोग शामिल हो। मॉस्को, अपनी तरफ से, भारत को एक भरोसेमंद भागीदार के तौर पर बनाए रखने में फ़ायदा देखाता है, ऐसे समय में जब उसके अपने रणनीतिगत माहौल पर काफी दबाव पड़ा है। पश्चिमी पाबंदियों और बदलते क्षेत्रीय गठबंधनों ने रूस को अपने आर्थिक और राजनीतिक जुड़वां में विविधता लाने के लिए मजबूर किया है। भारत का बड़ा बाज़ार, इसका बढ़ता रक्षा औद्योगिक आधार और इसका भूराजनीतिक वजन रूस को स्थिरता और मौका दोनों देते हैं। आने वाला शिखर स मेलन इन मेलजोल को मजबूत करने का एक रास्ता देता है, मौजूदा संबंधों और उत्पादनों पर काम करते हुए भविष्य के ऐसे रास्ते बताता है जो साझा रणनीतिगत गणना को दिखाते हैं।

इन बातों का नई दिल्ली की विदेश नीति के लिए भी बड़े असर हैं। रणनीतिगत स्वायत्तता पर भारत का लंबे समय है जोर, बदलते वैश्विक शक्ति ढांचा द्वारा लगातार जांचा जा रहा है। अमेरिका–चीन तनाव के बदलते हालात, अन्तरराष्ट्रीय प्रणाली में रूस की बदलती स्थिति और पश्चिम एशिया को आकार दे रही अनिश्चितताओं ने भारत की राजनयिक फुर्ती पर नई मांगें खड़ी कर दी हैं। इस माहौल में, रूस के साथ एक मजबूत भागीदारी बनाए रखने से कई मकसद पूरे होते हैं= यह भारत

की पैंतरेबाज़ी की आज़ादी बनाए रखने में मदद करता है, इसके रक्षा प्रदर्शन में विविधता पक्का करता है और दूसरी बड़ी ताकतों के साथ बातचीत में फ़ायदा देता है। इनमें से कई गणनाओं के साथ ऊर्जा सुरक्षा जुड़ी हुई है। भारत की विविधिकरण रणनीति का मतलब है कि कोई भी एक देश इसके आपूर्ति स्रोत पर हावी नहीं है, लेकिन रूस एक अहम भूमिका निभाता रहा है।

इसका हेवी करूड भारत के रिफ़ाइनिंग इकोसिस्टम में सटीक बैठता है, जबकि अमेरिकी लाइट करूड लोच और माप की अधिकता देता है। जैसे-जैसे वैश्विक बाजार ओपेक के व्यवहार में बदलाव, गैर–ओपेक आपूर्ति के विस्तार और कमोडिटी के बहाव को प्रभावित करने वाली बड़ी अस्थिरता के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, भारत के आयात प्रोफ़ाइल में रूसी और अमेरिकी करूड के बीच टकराव की कमी दोनों भागीदार के साथ समानांतर स बंध कायम रखने के लिए जगह देती है। इसने न केवल भूराजनीतिक जोखिमों को कम किया है, बल्कि भारत की ऊर्जा राजनयिकता को आगे बढ़ाने की क्षमता को भी गहरा बढ़ाया है जो व्यावहारिक और लचीली दोनों है। शिखर स मेलन में होने वाली चर्चाओं में बड़ी आर्थिक संभावनाओं पर भी बात होने की संभावना है, भले ही रक्षा और ऊर्जा सुर्खियों में छाप रहें। दोनों देशों के बीच व्यापार के आंकड़ों में पहले वृद्धि में तेज़ी दिखी, फिर कुछ समय के लिए ठहराव भी आया, जो लगातार बढ़ोतरी को अनलॉक

करने के लिए ढांचागत दखल की ज़रूरत को दिखाता है। कनेक्टिविटी की दिक्रतें, निर्यात की टोकरी में सीमित विविधता और नियामक अवरोधों ने पारंपरिक रूप से तरक्की में रुकावट डाली है। मौजूदा माहौल में, जहां सप्लाई चेन की जोखिमों को कम कर उसे बेहतर बनाना वैश्विक प्राथमिकता बन गयी है, भारत और रूस द्विपक्षीय व्यापार को स्थिर करने के तरीके खोज सकते हैं। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, खनिज संसाधन और नाभिकीय प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाना शामिल हो सकता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहले से ही स पूरक चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा, जिस भूराजनीतिक पृष्ठभूमि में यह शिखर स मेलन हो रहा है, वह दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रकृति तय कर रहा है।

भारत की पश्चिमी भागीदारी और रूस के साथ अपनी पार परिक दोस्ती के बीच लगातार संतुलन बनाना एक बारीक काम है। नई दिल्ली ने बड़ी ताकतों के ध्रुवीकरण में फंसेने से बचने के बजाय, अपने रणनीतिगत हितों को आगे बढ़ाने के लिए कई कर्ताधर्ताओं के साथ अपने रिश्तों का फायदा उठाया है। वाशिंगटन में तेल से जुड़े तनाव में कमी ने इस संतुलन के काम में आत्मतोष की एक परत को कम कर दिया है। इससे भारत मॉस्को के साथ शिखर स मेलन में ज्यादा आत्मबल के साथ जा सकता है, यह जानते हुए कि वह दूसरे भागीदारों के साथ रिश्तों में तनाव डाले बिना अपने संबंधों को बचा सकता है। रूस भी भारत

के पैंतरेबाज़ी की आज़ादी बनाए रखने में मदद करता है, इसके

आसानी से दिखे और सुलभ हो। इसकी कार्यक्षमताओं को अक्षम या प्रतिबंधित न किया जाए। इस निर्देश से साफ है कि मंत्रालय ने ऐप को हटाने पर रोक लगाई है। तो लोग मंत्रालय के निर्देश मानें या मंत्री की मुंहजुबानी बात पर यकीन करें? डिजिटल अधिकार वकालत संगठन, इंटरनेट फ्रीडम फ़ाउंडेशन (आईएफएफ) ने सिंधिया की टिप्पणियों का खंडन करते हुए कहा है कि स्पष्टीकरण गलत है% और आधिकारिक निर्देश स्पष्ट रूप से कहता है कि संचार साथी को %अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है%। आईएफएफ ने यह भी कहा है कि पर्सनल डिजिटल डिवाइस पर सरकारी कंट्रोल का तेज़ी से बढ़ना बहुत चिंता की बात है। ऐसे फैसले कानूनी तौर पर कमजोर हैं, और यूज़र की निजता के लिए खतरनाक है। सरकार का यह आदेश संविधान के भी खिलाफ है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार डिजिटल और टेलिकॉम से जुड़े फ़ैसले केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन साइबर अपराध को रोकना राज्यों की जि मेदारी है। जब केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार अलग–अलग हैं, तो कोई नया नियम बनाने से पहले राज्यों और आम लोगों से सलाह–मशविरा क्यों नहीं किया गया?

यह एक बड़ा सवाल है। बता दें कि भारत में डेटा प्रोटेक्शन कानून 2023 में साफ़ लिखा है कि किसी भी तरह का व्यक्तिगत डेटा लेने के लिए सहमति ज़रूरी है। लेकिन यहां तो सरकार बिना यूज़र की मर्जी के उसके फोन में घुसने की कोशिश कर रही है। फोन में क्या रहेगा और क्या नहीं, यह तय करने का अधिकार हमारी निजी स्वतंत्रता का हिस्सा है। ऐसे में, अगर संचार साथी ऐप को फोन से हटाने का विकल्प नहीं मिलेगा तो यह यूज़र की निजता, स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ माना जा सकता है। सबसे अच्छा स्मार्टफोन यह बताने की ज़रूरत नहीं कि मोबाइल फोन सबकी पर्सनल स्पेस होती है। एक घर के सदस्य ही एक–दूसरे से अपने मोबाइल फोन के पासवर्ड साझा नहीं करते हैं। भले कुछ छिपाने को न हो, फिर भी एक–दूसरे के फोन पर झांकना बदतमीजी समझा जाता है। क्योंकि यहां निजी बातें होती हैं, कई ज़रूरी नोट्स संभाल कर रखे जाते हैं। यादगार तस्वीरें होती हैं। जैसे पहले लोग डायरी लिखते थे और किसी की डायरी पढ़ना खराब आदत मानी जाती थी, वही व्यवहार अब मोबाइल के साथ हो चुका है। ऐसे में संचार साथी ऐप मोबाइल में होने के बाद खतरा बना रहेगा कि यह ऐप हमारे फ़ोन की फ़ाइलें, फोटो या मैसेज देख लेगा या भविष्य के किसी अपडेट में ऐसा कर सकता है। अभी भले ही सरकार इसे डिजिटल सुरक्षा का औजार बता रही है, लेकिन असल में इसी औजार से सबसे ज्यादा संघर्ष लगने का खतरा रहेगा, ऐसा जानकारी मान रहे हैं। संचार साथी ऐप से अनेक प्रकार का डेटा सरकार के पास आएगा और आज की तकनीकी क्षमता वाली पूंजीवादी राजनीति में डेटा ही सबसे बड़ी संपत्ति किसी देश के लिए बन चुका है।



नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने अपने पार्षदों के साथ वार्डों में किया बूथ स्तरीय निरीक्षण

कवर्धा ०४/१२ (संवाददाता): नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने अपने पार्षदों के साथ नगर के विभिन्न वार्डों के बूथों का निरंतर दौरा कर रहे हैं। दोरे के दौरान उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर्स से मुलाकात कर मतदाता सूची के शत-प्रतिशत परीक्षण एवं पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची में नाम आवश्यक-चंद्रप्रकाश निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती हर पात्र व्यक्ति के मतदाता सूची में दर्ज होने से

पुनरीक्षण अभियान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित समय-सीमा में संचालित किया जाएगा। उन्होंने पार्षदों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने वार्डों में नागरिकों को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प्रति जागरूक करें और अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का नाम जुड़वाने में सहयोग दें। समस्याओं का किया निराकरण इस दौरान नगर के अनेक नागरिकों ने मतदाता सूची से संबंधित अपने प्रपत्र एवं समस्याएं भी प्रस्तुत कीं, जिनका तत्काल निराकरण किया गया। बीएलओएस को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा

गया कि नए पात्र मतदाता (18+) का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए, पात्र महिला मतदाताओं एवं वरिष्ठ नागरिकों का नाम सूची में पूर्ण रूप से दर्ज हो, किसी भी कारण से छूटे हुए नामों का फॉर्म-6, 7, 8 के माध्यम से अद्यतन किया एवं घर-घर सत्यापन अभियान को और गति प्रदान किए जाने को कहा। निरीक्षण के दौरान पार्षदों सहित नगर के बुद्धिजीवी, व्यापारी एवं महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उन्होंने प्रशासनिक टीम को सहयोग प्रदान किया। नपाध्यक्ष

चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने की अपील नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण कार्य है उन्होंने कवर्धा शहर के नागरिकों को अपील किया है कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम जारी है आपके वार्ड में एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा मतदाता सूची परीक्षण संबंधी जानकारी दी जायेगी एवं प्रपत्र फर्म भी दिया जायएल रहा है जिसे सावधानी पूर्वक भरकर संबंधित के पास ही जमा करें।



लोकेशन ट्रैक की गई। सुराग मिलने पर तीन टीमों अलग-अलग दिशाओं में रवाना की गई। पहला आरोपी कुंवर सिंह भदौरिया (31 वर्ष) को नागपुर से उस समय पकड़ा गया, जब वह गोवा से भिंड लौटने की कोशिश में था। दूसरा आरोपी अमरपाल सिंह (30 वर्ष) रायगढ़ से गिरफ्तार हुआ। इनके कज्जे से एयर पिस्टल और छर्रे बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकारते हुए बताया कि वे भिंड (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं और ट्रक से ज़लाई ऐश बुलाई के दौरान धमतरी आते-जाते थे। इसी दौरान दुकान की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे लगातार शहर, राज्य और मोबाइल बदलते रहे तथा पुलिस गतिविधियों पर नजर रखते रहे। पुलिस की लगातार तकनीकी और जमीनी रणनीति से यह मामला सुलझा और आरोपी पकड़े गए। इस कार्रवाई ने व्यापारियों में राहत और अपराधियों में भय का संदेश दिया है। लंबित वादे की पूर्ति पर भंवरलाल बरडिया ने पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार और पूरी टीम की प्रशंसा की।

रायपुर के आसमान में दिखी चमकदार कतार, लोगों में कौतूहल—स्टारलिनक सैटेलाइट निकला कारण

रायपुर ०४/१२ (संवाददाता): राजधानी में रविवार शाम आसमान में दिखाई दिया अनोखा नजारा चर्चा का विषय बन गया। शहर के कई इलाकों में लोगों ने आकाश में चमकते बिंदुओं की लंबी श्रंखला को एकसाथ आगे बढ़ते देखा, जो कुछ देर बाद धीरे-धीरे ओझल हो गई। अचानक दिखाई दी इस रोशनी ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का ध्यान खींच लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चमकदार कतार बिल्कुल ट्रेन के डिब्बों जैसी प्रतीत हो रही थी। उत्सुक लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो और तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दीं। इसके बाद तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं—किसी ने इसे ख़ह से जोड़ा, तो किसी ने इसे बाहरी ग्रहों से जुड़ी गतिविधि माना। बाद में

विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट किया गया कि आसमान में दिखाई दी यह रोशनी किसी रहस्यमयी घटना का नहीं, बल्कि एलन मस्क की स्टारलिनक परियोजना के सैटेलाइट्स का परिणाम था। स्पेसएक्स द्वारा संचालित यह तकनीक दुनिया भर में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात कर रही है। सूर्य की रोशनी इनके सतह पर पड़ने पर वे धरती से चमकदार कतार के रूप में दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसी दृश्यावली पूरी तरह सामान्य है और इससे पहले देश के अन्य राज्यों—जैसे पंजाब और जम्मू—में भी इसी तरह की चमक दिखाई दे चुकी है। रायपुर में यह दृश्य न सिर्फ उत्सुकता का कारण बना, बल्कि लोगों में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर समझ और जिज्ञासा भी बढ़ा गया।

चिकित्सा सेवाओं के बाजारीकरण के विरुद्ध समाज

भिलाई ०४/१२ (संवाददाता): इस्पात नगरी भिलाई के जाने-माने रंगकर्मी और फिल्मकार गुलाम हैदर मंसूरी की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म ‘मानव मार्केट’ रिलीज के लिए तैयार है। इसका टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। अब एक दिसंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है, वहीं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में फिल्म की रिलीज 19 दिसंबर 2025 को रखी गई है। यह फिल्म चिकित्सा सेवाओं के बाजारीकरण के विरुद्ध जन जागरूकता के मकसद से बनाई गई है। ‘मानव मार्केट’ के निर्माता गण कैलाश

चंद्र अग्रवाल और निज्मी रोशन सावने बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर फिल्म बनाने का प्रयास किया गया है ज्योंकि यह एक ऐसा विषय है, जिससे समाज का हर वर्ग प्रभावित है। निर्मातागण का कहना है कि चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में जिस तरह एक तबका लूट पर उतारू है, उसके विरुद्ध आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है। निर्माता कैलाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कोरोना काल में वह स्वयं भी चिकित्सा पेशे के बाजारीकरण के भुक्तभोगी रहे हैं और उनका मकसद है कि इस लूटपाट पर रोक लगनी चाहिए। निर्देशक

गुलाम हैदर मंसूरी ने बताया कि ‘मानव मार्केट’ बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम सभी समाज में बढ़ती बाजारवाद की सोच के खिलाफ एकजुट और जागरूक रहें। जिससे स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ समाज के हर तबके को बराबर मिले। फिल्म में ओम त्रिपाठी, नेहा शुक्ला, बाली कुर्रे, योगेश अग्रवाल, सुरेश गोंडाले, प्रिया शर्मा, हर्षा सहारे, आरुषि पॉल, विनायक अग्रवाल, मुस्कान खान, शहाना परवीन, अनूप रे, देवेंद्र मोयल, मनोज शर्मा और हनी शर्मा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। ‘मानव मार्केट’ के निर्देशक गुलाम हैदर मंसूरी और निर्माता कैलाश चंद्र

अग्रवाल व निज्मी रोशन सावने ने उम्मीद जताई है कि दर्शक उनकी इस फिल्म को भरपूर प्यार देंगे। वान्या फिल्म्स प्रोडक्शन, निज्म फिल्म्स प्रोडक्शन और भिलाई टॉकीज पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता कैलाश चंद्र अग्रवाल, निज्मी रोशन सावने और गुलाम हैदर मंसूरी, निर्देशक-गुलाम हैदर मंसूरी, रिलीजिंग पार्टनर-मेघा अग्रवाल, डी.ओ.पी-राजकुमार बघेल और एम.डी. फिरोज कुर्ैशी, कैमरा : रेड ड्रैगन विद अल्ट्रा प्राइम लेंस, स्टोरी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग गुलाम हैदर मंसूरी, एडिटिंग और डीआई सतीशा देवांगन,

वंदे मातरम् केवल उद्घोष नहीं दुनिया के शीर्ष 10 गीतों में सर्वाधिक लोकप्रिय दूसरा गीत

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में जब 7 नवंबर, 1876 में वंदे मातरम् गीत की रचना की तब उनके मानस में शायद ही यह होगा कि यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन में आजादी के दिवानों का प्रेरक होने के साथ ही आजादी के बाद भी देश की राष्ट्रीय एकता और मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक बन जाएगा। वंदे मातरम् में जिस तरह से माँ भारती

की स्तुति की गई है वह हमारी पहचान और गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत से रुबरु कराने का माध्यम बन गई। 1870 के भयंकर अकाल और अंग्रेजों द्वारा महारानी की शान में गौड़ सेव क्वीन के लिए बाध्य करने की प्रतिक्रिया के रूप में वंदे मातरम् की आधार भूमि तैयार हुई। कुछ समय बाद ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम् को प्रमुख स्थान दिया गया। आनंद मठ भी गुलामी से मुक्ति और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना से

ओतप्रोत उपन्यास होने से आजादी के आंदोलन ही नहीं आज भी प्रेरणा का स्रोत है। आनंद मठ में भवानन्द संन्यासी संन्यासी विद्रोहियों का नेतृत्व करते हुए यह गीत गाते हैं। वंदे मातरम् गीत की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि गुरुवर रविन्द्र नाथ टैगोर ने 1896 के कांग्रेस के सम्मेलन में इसे अपने स्वर देते हुए स्वयं गाया। उसके बाद तो वंदे मातरम् भारत की आत्मा ही बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के लिए तो वंदे मातरम् जयघोष ही बन गया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध का मार्च गीत ही वंदे मातरम् रहा। हालांकि वंदे मातरम् को लेकर मुस्लिम लीग आदि ने सांप्रदायिकता, धर्म विशेष से प्रेरित और मां दुर्गा को लेकर विरोध व्यक्त किया गया और यही कारण रहा कि वंदे मातरम् गीत के आरंभिक दो छंदों को ही कांग्रेस द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकारा गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि आजादी के अमृत काल में हम वंदे मातरम्

के 150 वें वर्ष को मनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात में देशवासियों से संवाद कायम करते हुए वंदे मातरम् के 150 वें वर्ष पर आयोजनों की श्रृंखला के माध्यम से आज की पीढ़ी को वंदे मातरम् के इतिहास और प्रेरकता से रुबरु कराने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम् भले ही 19 वीं शताब्दी में लिखा गया था लेकिन इसकी भावना भारत के हजारों वर्ष



राज्यव्यापी अभियान में अवैध गांजा खेती पर कार्रवाई

भुवनेश्वर ०४/१२ (संवाददाता): ओडिशा पुलिस ने गैर-कानूनी भाग की खेती के खिलाफ पूरे राज्य में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। स्पेशल टास्क टीम, ड्रोन, सैटेलाइट और इंटेलिजेंस पर आधारित निगरानी का इस्तेमाल करके मिलकर किए गए ऑपरेशन के ज़रिए कई जिलों में हजारों एकड़ गैर-कानूनी खेती को खत्म कर दिया गया है। लोगों की भलाई और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के मकसद से, प्रभावित जिलों में पुलिस यूनिट्स ने खास टीमें बनाई हैं जो खासकर दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में गैर-कानूनी भाग के खेतों का पता लगाकर उन्हें खत्म करना जारी रखती हैं। यह चल



रही कोशिश राज्य के इतिहास के सबसे बड़े एंटी-नारकोटिक्स कैम्पेन में से एक है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, 2025 तक 18,111 एकड़ से ज्यादा भाग की खेती पहले ही खत्म कर दी गई है, और यह कैम्पेन मार्च

2026 तक जारी रहने वाला है। इस साल नवंबर के आखिर तक, पूरे ओडिशा में मारिजुआना तस्करी से जुड़े 473 मामले दर्ज किए गए थे। ओडिशा के डायरेक्टर जनरल

ऑफ पुलिस योगेश बहादुर खुरानिया ने इस तेज़ी से हो रही तरक्की की तारीफ करते हुए कहा कि इतने कम समय में बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी खेती को खत्म करना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने भरोसा

दिलाया कि आने वाले महीनों में भी यह कैम्पेन इसी सज्जी से जारी रहेगा। इसकी तुलना में, 2024 में 594 केस रजिस्टर हुए थे, और पूरे राज्य में 20,803 एकड़ से ज्यादा भाग के बागान खत्म कर दिए गए थे। रायगढ़ा, मलकानगिरी, कोरापुट, बौध, कंधमाल, गजपति, गंजम और नबरंगपुर में गैर-कानूनी खेती की खबरें आ रही हैं। पुलिस छिपे हुए खेतों की पहचान करने और उन्हें खाली कराने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन सर्विलांस का इस्तेमाल कर रही है। छतक खुरानिया ने दोहराया कि मारिजुआना की खेती करने या प्रोडक्शन में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सज्ज कार्रवाई की जाएगी।

आरएसपी की 'उत्कर्ष' सुरक्षा चक्र टीम ने आईसीज्यूसी-2025, दुबई में प्रतिष्ठित 'पार एक्सीलेंस गोल्ड अवार्ड' जीता



राउरकेला ०४/१२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के ज़्लास्ट फर्नेस-5 की 'उत्कर्ष' सुरक्षा गुणवत्ता चक्र टीम ने दुबई में आयोजित इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स (आईसीज्यूसी) 2025 में पार एक्सीलेंस गोल्ड अवार्ड जीतकर कंपनी का नाम रोशन किया है। पुरस्कार विजेता टीम में इंजीनियरिंग सहायक एवं टीम लीडर, श्री संतोष कुमार

राय, कनिष्ठ इंजीनियरिंग सहायक एवं डिप्टी लीडर, श्री सुशांत स्वाई, इंजीनियरिंग सहायक, श्री दीपक दास तथा इंजीनियरिंग सहायक, श्री सरोज नायक शामिल थे। ज़्लास्ट फर्नेस-5 के उप प्रबंधक, श्री विक्रम झा टीम के मददकर्ता फ़ैसिलिटेटर थे। टीम को यह सम्मान ज़्लास्ट फर्नेस-5 के यु-सील क्षेत्र में लागू की गई कई नवोन्मेषी और प्रभावशाली सुरक्षा सुधार पहल

हेतु प्राप्त हुआ। इन पहलों ने जोखिम खतरों को उल्लेखनीय रूप से कम किया है और एक अत्यंत महत्वपूर्ण संचालन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को मजबूत किया है। यह उपलब्धि आरएसपी की सतत सुधार के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, कर्मचारियों की नवीन सोच को प्रोत्साहन, और कार्यस्थल सुरक्षा को सर्वोपरि रखने की संस्कृति को दर्शाती है।

बालासोर बीच पर 50 क्विंटल से ज्यादा वज़न वाली बड़ी व्हेल शार्क की लाश मिली

बालासोर ०४/१२ (संवाददाता): बालासोर के भोगराई समुद्र तट क्षेत्र में तलासरी में 30 फीट से अधिक लंबाई वाली एक विशाल व्हेल शार्क का शव मिला। मछली का वजन 50 क्विंटल से अधिक होने का अनुमान है, यह इस क्षेत्र में देखी जाने वाली अपने आकार की पहली मछली है, जिसने निवासियों और आगंतुकों दोनों का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्टों के अनुसार, भोगराई में सहबाजीपुर के पांच मछुआरे बुधवार सुबह मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे। उन्होंने किनारे से लगभग 700 फीट दूर अपना जाल डाला, और इसे खींचने की प्रक्रिया के दौरान व्हेल शार्क अन्य मछलियों के



साथ उलझ गई। जब तक इसे करीब लाया गया, तब तक मछली मर चुकी थी। मछुआरों ने पहले व्हेल शार्क को मैनुअल रूप से किनारे पर खींचने का प्रयास किया, लेकिन इसके आकार और वजन के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहे। लेकिन, जब मछली किनारे से करीब 50 फीट दूर पहुँची, तो कम गहरे पानी की वजह से उसे और आगे खींचना नामुमकिन हो गया। मछुआरों

और आस-पास के लोगों समेत करीब 100 लोगों ने मछली को बीच पर खींचने की कोशिश की, लेकिन बार-बार कोशिश करने के बाद भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तब से इस बड़ी व्हेल शार्क की मौजूदगी ने टूरिस्ट और आस-पास के लोगों की बड़ी भीड़ को अपनी ओर खींचा, और कई लोग इस अनोखी चीज़ की एक झलक पाने के लिए उस जगह पर आए।

कांग्रेस विधायकों ने आरक्षण के मुद्दे पर विस में विरोध प्रदर्शन किया



भुवनेश्वर ०४/१२ (संवाददाता): कांग्रेस ने गुरुवार को ओडिशा असेंबली में रिजर्वेशन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्पीकर को कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जैसे ही सदन प्रश्नकाल के लिए शुरू हुआ, कांग्रेस के सदस्य वेल में आ गए और राज्य की ऋक्षसरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे, उनका आरोप था कि डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है। वे राज्य में आबादी के हिसाब से

SC, ST और OBC के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करने के लिए पार्टी द्वारा एक प्रस्ताव पेश करने की इजाजत न दिए जाने का भी विरोध कर रहे थे। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नेता राम चंद्र कदम ने सदन में यह मुद्दा उठाया और कहा कि उन्होंने बुधवार को सदन में स्ख, स्ख और ह्छष्ट के लिए रिजर्वेशन पर एक प्रस्ताव पेश करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई। कांग्रेस के रूने नारे लगाए, और ऋक्षसरकार पर सदन में

विपक्षी सदस्यों के अधिकारों को नकारने का आरोप लगाया। सदन चलाने में असमर्थ, स्पीकर सुरमा पाधी ने कार्यवाही सुबह 10.46 बजे से 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बाद में, स्पीकर ने अपने चैंबर में ऋक्ष लीडर के साथ मीटिंग की और रू सुबह 11.30 बजे फिर से इकट्ठा हुए। फिर से, कांग्रेस के विधायकों ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए।

शुरू किया, लेकिन इनोवेशन में उनकी दिलचस्पी उनके स्कूल के दिनों से है, जहाँ उन्होंने साइंस एग्जिबिशन में हिस्सा लिया था। अपने सफर के बारे में बात करते हुए, जितेंद्र ने कहा कि उन्हें उत्साह है कि अगर उन्हें पैसे की मदद मिली तो वे इनोवेशन करते रहेंगे। उनका सपना एक कम लागत वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है जो लोगों को सस्ते में सफर करने में मदद कर सके। मैंने सबसे पहले एक रेलवे अधिकारी के घर छपा

भुवनेश्वर ०४/१२ (संवाददाता): आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में भुवनेश्वर के एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी के कई ठिकानों पर बुधवार सीबीआई की टीमों ने छापेमारी की है। सीबीआई भुवनेश्वर समेत 4 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। सीबीआई की 5 टीमों भुवनेश्वर में 2ए कटक में एक और जगतसिंहपुर में एक जगह एक साथ जांच कर रही हैं।

छापेमारी के दौरान सीबीआई को इमरजेंसी कागजातए के शाए बैंक डिपॉजिटए पासपोर्टए सोने के जेवरातए वाहनए जमीन के कागजात और ज़लैट मिले। सीबीआई ने जिसके घर छपा मारा है उसका नाम प्रमोद जेना है। प्रमोद जेना ईस्ट कोस्ट रेलवे के पूर्व प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक थे। सीबीआई की यह छापेमारी आय से 1 करोड़ 92 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति रखने के मामले में हुई है।

आरएसपी के सिंटरिंग प्लांट-१ के महा मरामज़ी अभियान में बड़े उन्नयन और ओवरहॉलिंग सफलतापूर्वक संपन्न

राउरकेला ०४/१२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के सिंटरिंग प्लांट-१ (एसपी-१) का महामरामज़ी, जो किया गया था, उच्च तकनीकी गुणवत्ता, उत्कृष्ट समन्वय और कड़ी सज्ज सुरक्षा अनुपालन के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस बड़े मरम्मत की कार्यक्रम में सिंटर प्लांट की विश्वसनीयता और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी कई महत्वपूर्ण तकनीकी और संरचनात्मक हस्तक्षेप शामिल थे। शटडाउन के दौरान किए गए मुख्य कामों में इंस्ट्रुमेंटेशन और ऑटोमेशन विभाग के विशेष सहयोग से प्रोसेस ऑटोमेशन को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ी पीपल्स उन्नयन, एीएमडी लाइनर प्रतिस्थापन और यूनिट 45 और 45क में लाइनर प्रतिस्थापन के साथ पैलेटाइजिंग ड्रम शेल का एक्स्टेंशन शामिल था। इन सभी कामों के लिए बहुत



सावधानी से इंजीनियरिंग और प्लानिंग की ज़रूरत थी। टीम ने एयर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मेन ज़्लोअर-2 का इन्पेलर भी बदला, कई मटेरियल-हैंडलिंग बेल्टों का नवीनीकरण और एक नई कोल्ड स्क्रीन डेक प्लेट लगाई। सिंटर ब्रेकर यूनिट, कोल्ड स्क्रीन इक्विपमेंट को बदलने और ऊपर और नीचे के बीम को नया करने से सिस्टम की स्टेबिलिटी और मजबूत हुई। दोनों फर्नेस में रिफ़ैक्ट्री रीलाइनिंग की गई जिससे तापीय दक्षता सुनिश्चित हो सके।। गैस सिस्टम को नया बनाने के हिस्से के तौर

पर, 900-एमएम डायमीटर की 53 मीटर और 350-एमएम डायमीटर की 50 मीटर गैस लाइनें बदली गईं। ईएसपी एमिटिंग इलेक्ट्रोड बदले गए, लगभग 250 मीटर पैन कन्वेयर रेल को नया किया गया, और सज़शन लाइनों में कई लीकेज पॉइंट्स की मरम्मत की गई, जिससे प्लांट का काम आसानी से और सुरक्षित तरीके से चलता रहा। मरम्मत का काम एसपी-1 के अधिकारियों, कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर एजेंसियों की मेहनत से पूरा हुआ। कामों को एसपी-1 की समर्पित टीम ने समय पर पूरा किया, जिसका

नेतृत्व महाप्रबंधक प्रभारी (एसपी-1), श्री शुभांशु चक्रवर्ती कर रहे थे, और इसकी लगातार निगरानी और मार्गदर्शन मुख्य महाप्रबंधक (सिंटर), श्री शेखर नारायण कर रहे थे। 1965 में शुरू हुआ एसपी-1, आरएसपी के सिंटरिंग संचालन की एक अभिन्न इकाई है। नवीनतम उपकरण उन्नयन और स्वचालन सुधारों के साथ एसपी-1 अब बेहतर उत्पादकता, उन्नत प्रक्रिया नियंत्रण और ज्यादा परिचालन दक्षता के लिए अच्छी स्थिति में है।